प्रेम नाथ और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

15 मार्च, 1967

[के.सुब्बा राव, मुख्य न्यायधीश, जे.सी. शाह, जे.एम. शेलट, वी. भार्गव और जी. के मिटर, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान अनुच्छेद 233– चयन समिति जिसमें प्रमुख शामिल हैं न्यायमूर्ति और केवल दो अन्य न्यायाधीश– पात्र उम्मीदवारों की सूची किसके द्वारा तैयार की गई है–यदि उचित परामर्श हो तो उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित समिति।

अनुच्छेद 233 ए– अधिनियम के तहत सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा यदि मान्य है।

अनुच्छेद 236– सिविल न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1955– यदि "जिला न्यायाधीश" लेख की परिभाषा के भीतर।

राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1955 में प्रावधान था कि उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई पात्र उम्मीदवारों की सूचियों में से की जानी थी, लेकिन उच्च न्यायालय की एक चयन समिति द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय।जब भर्ती होती है सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पदों को इस प्रक्रिया के अनुसार बनाया गया था, उन्हें इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि नियम संविधान के अनुच्छेद 233 का उल्लंघन किया। उच्च न्यायालय ने नियमों और उसके तहत की गई नियुक्तियों की वैधता को बरकरार रखा। इस अदालत में यह तर्क दिया गया था कि (i) नियम अनुच्छेद 233 के दायरे से बाहर थे, और (ii) सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का पद अनुच्छेद 236 में "जिला न्यायाधीश" की परिभाषा में शामिल नहीं है और इसलिए नियुक्तियां संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 233 ए द्वारा मान्य नहीं थीं।

अभिनिर्धारित किया गया: नियमों ने अनुच्छेद 233 का उल्लंघन किया और इसलिए नियुक्तियां अवैध थीं; लेकिन नियुक्तियों को अनुच्छेद 233 ए द्वारा मान्य किया गया था।

(i) अनुच्छेद 233 में यथा उपबंधित परामर्श उच्च न्यायालय के साथ परामर्श है, न कि नियमों के अधीन नियुक्त चयन समिति जैसे किसी अन्य प्राधिकारी के साथ। समिति, हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बनी है, उच्च न्यायालय नहीं है। नियमों के तहत उच्च न्यायालय को सौंपा गया एकमात्र कार्य समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को प्रेषित करना है और उच्च न्यायालय को सशक्त बनाने वाले नियमों में कुछ भी नहीं है। सूचियों को प्रस्तुत करने से पहले उन सूचियों को बदलने के लिए यदि उच्च न्यायालय समिति से असहमत था।

चंद्र मोहन v. उत्तर प्रदेश राज्य, [1967] आई.एस.सी.आर.: 77

(ii) जब किसी सिविल न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कि इस मामले में ठीक वैसा ही हुआ है, तो ऐसी नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जाती है। सिविल न्यायाधीश एक अतिरिक्त की शक्तियों का प्रयोग करता है।

सत्र न्यायाधीश इसलिए नहीं कि वह एक सिविल न्यायाधीश है, बल्कि इसलिए कि उसे एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए दोनों पदों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए, जब किसी व्यक्ति को एक साथ नियुक्त किया जाता है।

सिविल जज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में भी काम करने का इरादा है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत नियुक्ति की जानी है। इस तरह की नियुक्ति को अनुच्छेद 236 के अर्थ के भीतर "जिला न्यायाधीश" के अधीन आने वाली नियुक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 233 और राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम 1955 ऐसे पद पर लागू होते हैं, न कि अनुच्छेद 234 या राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955। इस तरह की नियुक्ति को अनुच्छेद 236 के अर्थ के भीतर "जिला न्यायाधीश" के अधीन आने वाली नियुक्ति के रूप में माना जाना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 233 और राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम 1955 ऐसे पद पर लागू होते हैं, न कि अनुच्छेद 234 या राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1966 की सिविल अपील संख्या 93

राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वितीय खंडपीठ द्वारा 27 नवंबर, 1964 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील: रिट याचिका संख्या 803 वर्ष 1964।

अपीलार्थी के लिए: एम. बी. एल. भार्गव और नौलत लाल।

राज्य पक्ष: भारत सरकार के सॉलिसिटर–जनरल एस. वी. गुप्ते (केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी), राजस्थान सरकार के अधिवक्ता–जनरल जी. सी. कटारिया और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए के. बी. देव मेहता।

सरजू प्रसाद, एस. एन. प्रसाद और ओ. सी. माथुर, प्रतिवादी संख्या 6 और 7 और हस्तक्षेपकर्ता संख्या 1 और 2 लिए।

आर. के. गर्ग, एस. सी. अग्रवाल और डी. पी. सिंह, हस्तक्षेपकर्ता नंबर 3 के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति शेलट द्वारा: उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शांति भूषण और हस्तक्षेप कर्ता संख्या 4 के लिए ओपी राणा। न्यायालय का निर्णय सहलात, जे. द्वारा सुनाया गया था। प्रमाण पत्र द्वारा की गई यह अपील दो प्रश्न उठाती है: (i) क्या राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1955 अनुच्छेद 233 के दायरे से बाहर है और इसलिए, उसके तहत नियुक्त चयन समिति द्वारा किए गए चयन और ऐसे चयनों के आधार पर की गई नियुक्तियां अमान्य हैं, और (2) यदि हां, तो क्या नियुक्तियां संविधान द्वारा मान्य हैं (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 जो संविधान में अनुच्छेद 233 ए पेश करता है।

9 मई, 1955 को तत्कालीन राजप्रमुख (भाग ब्) परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार, राजस्थान के अनुच्छेद 309 को प्रख्यापित किया गया न्यायिक सेवा नियम, 1955. उक्त नियमों के अनुसरण में, "राजस्थान उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर, 1963 को एक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के चार पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। उच्च न्यायालय को अनेक आवेदन प्राप्त हुए थे और उनकी संवीक्षा और आवेदकों को दिए गए साक्षात्कारों के बाद उक्त नियमों के अंतर्गत नियुक्त चयन समिति जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल थे,प्रशासनिक न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित, चार उम्मीदवारों का चयन किया। इन चार पदों के अलावा, पदोन्नति द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों में से चौदह पद भरे जाने थे। उक्त समिति ने उन सदस्यों में से पात्र उम्मीदवारों का चयन किया और एक और सूची तैयार की। उच्च न्यायालय ने समिति द्वारा तैयार की गई दो सूचियों को नियुक्तियों के लिए राज्यपाल को सौंप दिया।

अपीलकर्ताओं जो राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्य हैं, ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें किए गए चयन, आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियों की वैधता को चुनौती दी गई। चयन समिति और उन सूचियों के आधार पर की गई नियुक्तियां इस आधार पर की गई थीं कि वे अनुच्छेद 233 का उल्लंघन करके की गई थीं। उच्च न्यायालय ने उक्त नियम को वैध मानते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया, इसलिए, उक्त समिति की कार्यवाही, उसके द्वारा तैयार की गई और उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई सूचियां और की गई नियुक्तियां सभी वैध थीं। इसलिए यह अपील की गई है।

राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम का नियम 1(2) यह प्रावधान है कि उक्त नियम जिला और सत्र न्यायाधीशों और सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों से युक्त सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे। नियम 6 में प्रावधान है कि सेवा की संख्या और उसमें पदों के प्रत्येक वर्ग का निर्धारण राज्यपाल द्वारा समय–समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा।न्यायालय और सेवा की स्थायी संख्या और उसमें पदों के प्रत्येक वर्ग की संख्या अनुसूची I. उप–नियम (3) में निर्दिष्ट होगी।नियम 6 में राज्यपाल को समय–समय पर और उच्च न्यायालय के परामर्श से सेवा में किसी भी पद को खाली छोड़ने या स्थगित करने या ऐसे अतिरिक्त अस्थायी पद का सृजन करने की शक्ति प्रदान की गई है। सेवा में स्थायी पद जो आवश्यक पाए जाएं। अनुसूची I में 18 पर जिला और सत्र न्यायाधीशों की संख्या प्रदान की गई है, अर्थात, 15 न्यायाधीश, कानूनी स्मरणकर्ता का एक पद, एक पद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की संख्या, और संयुक्त कानूनी का एक पद 20 साल की उम्र में सिविल और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की याद दिलाता हूं। नियम 7 भर्ती के स्रोत प्रदान करता है, अर्थात्, राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा और उच्च न्यायालय के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा।सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति सात साल से अधिक के वकील या वकील हैं। नियम 10 निम्नानुसार है: –(ठ) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 7 में विनिर्दिष्ट दो स्त्रोतों में से प्रत्येक से प्रत्येक भर्ती में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और वह अवधि (तीन वर्ष से अधिक नहीं) जिसके लिए ऐसी भर्ती की जानी है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या कभी भी सेवा की कुल संख्या के एक–चौथाई से अधिक नहीं होगी और भर्ती की किसी एक अवधि के दौरान इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या उस अवधि के दौरान होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के एक–चौथाई से अधिक नहीं होगी। नियम 13 में प्रावधान है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में नियम 10 के तहत निर्णय लिए जाने के बाद,

राजस्थान न्यायिक सेवा के पात्र सदस्यों में से चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रमुख शामिल होंगे।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश, प्रशासनिक न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश। इसमें यह भी प्रावधान है कि समिति पात्र अधिकारियों में से उन अधिकारियों में से चयन करेगी जिन्हें वे सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानते हैं। चयनित अधिकारियों की एक सूची राजस्थान न्यायिक सेवा में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में बनाई जाएगी। जहां तक सीधी भर्ती का संबंध है, नियम 17 में प्रावधान है कि आवेदन किसके द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे. उच्च न्यायालय। नियम 21 में प्रावधान है कि चयन समिति ऐसे आवेदनों की जांच करेगी और ऐसे पात्र उम्मीदवारों की अपेक्षा करेगी जो सेवा में नियुक्ति के लिए सबसे योग्य लगते हैं। इन नियमों के तहत साक्षात्कार के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होना. नियम 22 के तहत चयन समिति को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होती है जिन्हें वे सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानते हैं। नियम 21 के तहत उच्च न्यायालय को विचार किए गए उम्मीदवारों की दो सूचियों में से दो–दो प्रतियां राज्यपाल को सौंपनी होती हैं।

नियम 13 और 22 के अनुसार तैयार भर्ती के दो स्रोतों से सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त। नियम 24 में प्रावधान है कि सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा नियम 13 के तहत तैयार की गई सूचियों से उम्मीदवारों को लेकर मूल रिक्तियों की घटना पर की जाएंगी।

नियम 22 उस क्रम में जिसमें वे संबंधित सूचियों में खड़े हैं। पहली तीन रिक्तियों को नियम 13 के तहत तैयार सूची से भरा जाएगा और चौथी रिक्ति को नियम 22 के तहत तैयार की गई सूची से भरा जाएगा। नियम 13(2) से स्पष्ट है कि इनमें से चयन उच्चतर सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों को चयन समिति द्वारा बनाया जाता है, न कि पूरे उच्च न्यायालय द्वारा, हालांकि समिति द्वारा इसके तहत तैयार की गई सूची को उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल को अग्रेषित किया जाता है। नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

13 या किसी अन्य नियम में उच्च न्यायालय को समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है या तो उन सूचियों में अन्य लोगों को प्रतिस्थापित करके जिन्हें उच्च न्यायालय अधिक उपयुक्त मानता है या समिति द्वारा चयनित और सूचियों में से किसी एक को वापस लेकर या हटाकर। जहां तक सीधी भर्ती का संबंध है, नियम 21 के अंतर्गत समिति इसकी जांच करती है। आवेदन और यह फिर से समिति है जो तय करती है कि कौन अस्वीकार करना और साक्षात्कार के लिए किसे बुलाना है. उच्च न्यायालय ने आवेदनों की जांच से कोई लेना–देना नहीं है। यह फिर से है चयन समिति जो नियुक्ति के लिए योग्य माने जाने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार करती है, न कि उच्च न्यायालय। यह चयन समिति भी है जो उनके द्वारा चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है। इसलिए, नियमों के तहत उच्च न्यायालय को सौंपा गया एकमात्र कार्य नियम 13 और 22 के तहत समिति द्वारा तैयार की गई दो सूचियों को प्रेषित करना है। जैसा कि पूर्वोक्त है, नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यपाल को सूचियां प्रस्तुत करने से पहले उच्च न्यायालय को उन सूचियों को बदलने का अधिकार देता हो, भले ही उच्च न्यायालय समिति द्वारा किए गए चयनों से असहमत हो। स्पष्ट तया यह समिति उच्च न्यायालय नहीं है। इस प्रकार उच्च न्यायालय केवल एक प्रसारण प्राधिकारी है। जैसा कि अनुच्छेद 233 में प्रावधान किया गया है, परामर्श उच्च न्यायालय के साथ परामर्श है, न कि नियमों के तहत नियुक्त चयन समिति जैसे किसी अन्य प्राधिकारी के साथ। इसलिए, नियम हैं अनुच्छेद 233 में दिए गए जनादेश के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है और इसलिए अमान्य हैं। नतीजतन, समिति द्वारा किए गए चयन, उनके द्वारा तैयार की गई सूचियां और की गई नियुक्तियां इसके तहत अमान्य होगा। हाल ही में, जिला न्यायाधीशों की भर्ती के लिए उत्तर

प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, जो इस अपील में नियमों के साथ लगभग समान नहीं थे, चंद्र मोहन v. उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए आए थे। उक्त नियमों के विश्लेषण के बाद, इस न्यायालय ने माना कि उक्त नियम अनुच्छेद 233 के अनुरूप नहीं थे और इसका उल्लंघन करते थे और आगे कहा कि इसके तहत की गई नियुक्तियां अवैध थीं।

अदालत ने कहा:

"अनुच्छेद 233 का संवैधानिक जनादेश स्पष्ट है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय के साथ उसके परामर्श से निर्धारित होता है, अर्थात्, वह केवल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। परामर्श का उद्देश्य स्पष्ट है। उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए न्यायिक सेवा या बार से संबंधित किसी व्यक्ति की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में राज्यपाल से बेहतर जानता हो। इस जनादेश को राज्यपाल द्वारा दो तरीकों से अवज्ञा किया जा सकता है; प्रत्यक्ष रूप से, उच्च न्यायालय से परामर्श न करके, और अप्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय और अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके। इस संवैधानिक जनादेश का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों महत्व है, यह संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 124 (2) और 217 (2) और 222 देखें। इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि परामर्श करने का कर्तव्य यह शक्ति के प्रयोग के साथ इतना एकीकृत है कि शक्ति का उपयोग केवल उसमें नामित व्यक्ति या व्यक्तियों के परामर्श से ही किया जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि:

"यूपी उच्च न्यायिक सेवा नियम संवैधानिक रूप से शून्य थे क्योंकि वे स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 233 (1) और (2) के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करते थे। नियमों के तहत, उच्च न्यायालय का परामर्श एक खाली औपचारिकता है। राज्यपाल योग्यता, चयन निर्धारित करता है। उनके द्वारा नियुक्त समिति उम्मीदवारों का चयन करती है और उच्च न्यायालय को समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों में से सिफारिश करनी होगी। यह संवैधानिक प्रावधान का उपहास है। राज्यपाल न तो उच्च न्यायालय से परामर्श करता है और न ही उसकी पुन: पुष्टि पर कार्रवाई करता है।

जाहिर है कि राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों के तहत आवेदनों की संवीक्षा, आवेदकों के साक्षात्कार, दोनों स्रोतों से पात्र उम्मीदवारों का चयन और दोनों सूचियों को तैयार करने का पूरा कार्य चयन द्वारा किया जाता है। समिति द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा नहीं। एकमात्र कार्य उच्च न्यायालय को नियमों के तहत विश्वसनीय समिति द्वारा तैयार दो सूचियों को राज्यपाल को प्रेषित करना है। इसलिए, नियमों में उच्च न्यायालय के परामर्श का प्रावधान नहीं है। इसलिए, न्यायालय अनुच्छेद 233 का उल्लंघन करता है जो उच्च न्यायालय के साथ परामर्श की परिकल्पना करता है, न कि किसी अन्य निकाय जैसे कि चयन समिति के साथ, जो उच्च न्यायालय का स्थान नहीं ले सकता है, भले ही उसके सदस्य उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश हों। राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर–जनरल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके लिए इन नियमों को यूपी उच्च न्यायिक सेवा नियमों से अलग करना संभव नहीं था और इसलिए, चंद्र मोहन के मामले में निर्णय वर्तमान नियमों पर लागू होगा। नतीजतन, उक्त नियम नहीं कर सकते हैं।

इसे बनाए रखा जाना चाहिए और अवैध घोषित किया जाना चाहिए। चयन समिति द्वारा की गई कार्यवाही और उनके बाद की गई कार्रवाई को भी अमान्य माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न यह है कि क्या नियुक्तियां सरकार द्वारा

की गई हैं उक्त सूचियों में से राज्यपाल किसके द्वारा मान्य है, संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 लेख 233A पेश किया गया। उक्त अधिनियम द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान है। "किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद कोई न्यायालय (a) (i) पहले से किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किसी राज्य या किसी ऐसे व्यक्ति की न्यायिक सेवा में जिसके पास कम से कम सात साल के लिए एक वकील या एक वकील वकील, उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश होना चाहिए, और (ii) नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति की तैनाती, पदोन्नति या स्थानांतरण। जिला न्यायाधीश, संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय बनाया गया । प्रावधानों के अनुसार अन्यथा अनुच्छेद 23 3 या अनुच्छेद 23 5 को अवैध माना जाएगा या शून्य या कभी भी केवल कारण से अवैध या शून्य हो जाना इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति या उक्त प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण नहीं किया गया था। इस प्रकार संशोधन जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति को मान्य करता है, यदि ऐसी नियुक्ति, अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के अनुसार नहीं होने के कारण, अवैध या शून्य होती। वकील द्वारा उठाया गया सवाल यह है कि क्या सिविल और अतिरिक्त के पद पर नियुक्ति सत्र न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश में से एक कहा जा सकता है।

अनुच्छेद 236 (ए) एक 'जिला न्यायाधीश' को परिभाषित करता है जिसमें न्यायाधीश भी शामिल है: एक सिटी सिविल कोर्ट, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, एक छोटे से कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। एक सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्पष्ट रूप से इस परिभाषा में शामिल न्यायिक अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों में स्थान नहीं मिलता है। अपीलकर्ताओं के लिए श्री भार्गव, इसलिए, तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 236, एक जिला न्यायाधीश को परिभाषित करते समय, इसमें एक सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शामिल नहीं है; इसलिए, सिविल और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति जिला न्यायाधीश नहीं है और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 233 ए सिविल और अतिरिक्त सत्र के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति को मान्य नहीं करता है। जज करें कि क्या वह नियुक्ति अवैध थी। अपने अच्छे बनाने के लिए उन्होंने राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 पर भरोसा किया, जिसकी धारा 6 में सिविल न्यायालयों की चार श्रेणियों का प्रावधान है, अर्थात (1) जिला न्यायाधीश की अदालत, (2) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत, (3) सिविल न्यायाधीश की अदालत, और (4) मुंसिफ की अदालत। अध्यादेश की धारा 13 में प्रावधान है कि सिविल न्यायाधीश के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति और मुंसिफ राजस्थान लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राजप्रमुख द्वारा उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए जाएंगे। धारा 19 में प्रावधान है कि सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के पास सिविल प्रकृति के सभी मूल मुकदमों और कार्यवाहियों को सुनने और निर्धारित करने का अधिकार होगा और मुंसिफ की अदालत के पास सिविल प्रकृति के सभी मूल मुकदमों और कार्यवाही को सुनने और निर्धारित करने का अधिकार होगा, जिसका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है। धारा 16 और 17 में न्यायालयों के बैठने और मुहरों के स्थान का प्रावधान है। 9 मई, 1955 को, राजस्थान के राजप्रमुख ने अनुच्छेद 234 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों को अनुच्छेद 238 और अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ प्रख्यापित किया। नियम 4 'सेवा के सदस्य' को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है इन नियमों के प्रावधानों के तहत या नियम 2 द्वारा प्रतिस्थापित किसी भी नियम या आदेशों के तहत सेवा के कैडर में एक पद पर मूल क्षमता में नियुक्त व्यक्ति। उस नियम के खंड (एफ) में 'सेवा' को राजस्थान न्यायिक सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। नियम 6 बताता है "सेवा की ताकत और यह प्रावधान है कि सेवा की ऐसी संख्या और उसमें पदों के प्रत्येक वर्ग का निर्धारण राजप्रमुख द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। उप-नियम (2) में

यह प्रावधान है कि सेवा की स्थायी संख्या और उसमें पदों के प्रत्येक वर्ग की स्थायी संख्या अनुसूची–। में विनिदष्ट होगी। उस अनुसूची के अनुसार, सिविल न्यायाधीशों के पदों की संख्या 30 और मुंसिफों के पदों की संख्या 80 निर्धारित की गई थी। भार्गव का तर्क था कि न तो राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियमों के तहत और न ही राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों के तहत, सिविल जज के पद पर रहने वाले व्यक्ति की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान है, कि जब प्रतिवादी 6 और 7 को नियुक्त किया गया था, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अतिरिक्त शक्तियों के साथ सिविल न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त, इसलिए, सिविल न्यायाधीश के रूप में वे राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955 के लिए उत्तरदायी होंगे। और राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियमों के लिए नहीं और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 233 ए उनकी नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 233 ए लागू होने से पहले, नियुक्ति होनी चाहिए जिला न्यायाधीश के पद के लिए और ऐसा नहीं है क्योंकि सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का पद अनुच्छेद 236 में 'जिला न्यायाधीश' की परिभाषा में शामिल नहीं है। श्री गर्ग उपस्थित हो रहे हैं हस्तक्षेपकर्ताओं ने तर्क दिया कि सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियां एक सिविल न्यायाधीश और एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद को एक साथ जोड़ती हैं, हालांकि इन पदों को एक साथ जोड़ा जाता है, ऐसी नियुक्तियां अनुच्छेद 234 द्वारा शासित होंगी, न कि अनुच्छेद 233 द्वारा और इसलिए अनुच्छेद 233 ए ऐसी नियुक्तियों को न तो लागू करेगा और न ही मान्य करेगा। उनके अनुसार, इस तरह की नियुक्तियां अनुच्छेद 234 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क देने की कोशिश की कि चूंकि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम "उत्तर प्रदेश से अलग नहीं थे। नियम अमान्य हैं, कि अनुच्छेद 233 ए ऐसे अमान्य नियमों को मान्य नहीं करता है और चूंकि उक्त नियुक्तियां अमान्य नियमों के तहत की गई हैं, इसलिए उन्हें अनुच्छेद 233A द्वारा ठीक नहीं किया गया था। हम इस स्तर पर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि अनुच्छेद 233 ए की संवैधानिक वैधता का सवाल इसमें नहीं उठाया गया है। नियुक्तियों को अमान्य के रूप में चुनौती दी जाती है क्योंकि वे अनुच्छेद 233 का उल्लंघन करके की गई थीं। अनुच्छेद 33 ए के प्रावधानों को चुनौती नहीं दिए जाने के कारण हमने हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश श्री गर्ग को इस अपील में उस प्रश्न पर विचार करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए, हम इस प्रश्न पर निर्णय लेने से पीछे हटते हैं।

इसके बाद श्री गर्ग ने हमें बंगाल, आगरा और असम का उल्लेख किया। सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887, जिसकी धारा 3 में सिविल न्यायालयों के उन्हीं चार वर्गों का प्रावधान है जैसा कि राजस्थान अध्यादेश की धारा 6 में किया गया है और श्री भार्गव ने तर्क दिया कि सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति काफी हद तक सिविल न्यायाधीश के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति है, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इसलिए, उन्होंने कहा, ऐसी नियुक्ति नहीं कही जा सकती है। अनुच्छेद 236 के अर्थ के भीतर एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होना। दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि सिविल और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का मतलब यह नहीं होगा कि वह केवल एक सिविल न्यायाधीश है या कि वह अनुच्छेद 236 द्वारा 'जिला न्यायाधीश' की परिभाषा में शामिल एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं है। ऐसे सिविल जज जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किए गए न्यायाधीश के पास सत्र न्यायाधीश की सभी शक्तियां होंगी और सत्र प्रभाग के सत्र न्यायालय में उनके पास वे सभी अधिकार क्षेत्र और शक्तियां होंगी जो एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास होंगी। दंड प्रक्रिया संहिता। विद्वान उप अधिवक्ता एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश जनरल ने सॉलिसिटर–जनरल का समर्थन किया और कहा कि अनुच्छेद 236 के तहत न्यायिक सेवा दो भागों में आती है। (i) एक सेवा जिसमें विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनका उद्देश्य जिले के पद को भरना है न्यायाधीश और

(2) जिला न्यायाधीश के पद से कम अन्य सिविल न्यायिक पद। उन्होंने "व्यक्तियों की नियुक्ति" शब्दों पर भरोसा किया अनुच्छेद 233 में प्रयुक्त जिला न्यायाधीश होना। उनके अनुसार, ये दो अनुच्छेद उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्हें पहली बार में जिला न्यायाधीश के पद से कम सिविल न्यायिक पदों पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन जिनका इरादा भविष्य में किसी समय जिला न्यायाधीश के पद को भरना है और इसलिए, ऐसे व्यक्ति भी जिला न्यायाधीश हैं और जिन पर अनुच्छेद 233 और 233 ए लागू होंगे। वर्तमान मामले में कला की व्याख्या और दायरे के प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं है। 233 और 236 जैसा कि श्री भार्गव द्वारा उठाया गया प्रश्न है। और श्री गर्ग को दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों पर विचार करके अच्छी तरह से हल किया जा सकता है। संहिता की धारा 6 में न्यायालयों के पांच वर्गों के लिए अलग-अलग प्रावधान है। उच्च न्यायालय से, अर्थात्, (1) सत्र न्यायालय, (2) प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, (3) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, (4) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, और (5) तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट।

धारा 7 में प्रावधान है कि प्रेसीडेंसी नगरों को छोड़कर प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग होना चाहिए या सत्र प्रभागों से मिलकर बनना चाहिए; और प्रत्येक सत्र प्रभाग, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा। धारा 9 में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए सत्र न्यायालय की स्थापना करेगी और ऐसे न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी। धारा 9 की उपधारा (3) राज्य सरकार को एक या अधिक ऐसे न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों और सहायक सत्र न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार देती है। धारा 36 में कहा गया है कि पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के जिला मजिस्ट्रेटों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों और मजिस्ट्रेटों को क्रमशः उन्हें प्रदान की गई शक्तियां होंगी और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट की जाएंगी। ऐसी शक्तियों को 'साधारण शक्तियां' कहा जाता है। धारा 37 अधिकृत करती है। राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, किसी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या पहली, दूसरी या तीसरी श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट को 'अतिरिक्त शक्तियां' प्रदान कर सकता है। धारा 39 के तहत, राज्य सरकार व्यक्तियों को नाम से या उनके पद के आधार पर या अधिकारियों के वर्गों को आम तौर पर उनकी आधिकारिक उपाधियों से ऐसी अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर सकती है। यह स्पष्ट है कि धारा 36 से 39 इन धाराओं के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त सिविल न्यायाधीश के मामले पर लागू नहीं हो सकती है।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जिलाधिकारियों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों और मजिस्ट्रेटों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने पर विचार। इसलिए, एक सिविल न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की शक्ति धारा 36 से 39 में नहीं बल्कि धारा 9 में पाई जानी है, जो पूर्वोक्त के रूप में राज्य सरकार को अतिरिक्त या अतिरिक्त नियुक्त करने का अधिकार देती है। राजस्थान सरकार की 2 जून, 1950 की अधिसूचना Rajasthan.By ठीक यही किया गया प्रतीत होता है। 1 जुलाई, 1950 से सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके कार्यालय के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होने का उल्लेख किया गया है जो सत्र न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो इसके कॉलम 2 में उल्लिखित हैं। इसलिए, जब एक सिविल न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जाता है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या जब किसी व्यक्ति को सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दोनों के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में ऐसी नियुक्ति शक्ति का प्रयोग करते हुए की जाती है। संहिता की धारा 9 के तहत। जब ऐसा सिविल न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह एक सिविल न्यायाधीश है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे संहिता की धारा 9 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया

है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों पदों को एक साथ जोड़ा गया है. तथ्यात्मक रूप से यह होता है कि एक व्यक्ति जो सिविल न्यायाधीश है या जिसे नियुक्त किया जाता है, उसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पहले सिविल न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है और फिर एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या क्या उन्हें एक ही समय में सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दोनों के रूप में नियुक्त किया जाता है। जब ऐसी नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्त व्यक्ति सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। शक्तियों के ऐसे संयोजन से एक ही व्यक्ति यह नहीं मानता है कि वह एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं है या वह एक सिविल न्यायाधीश है और इसलिए, 'जिला न्यायाधीश' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 236 (ए)। चूंकि ऐसा पद उस परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए यह होगा अनुच्छेद 233 और राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम जो उन पर लागू होंगे न कि अनुच्छेद 234 या राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955।

अनुच्छेद 233 और 234 में किसी न किसी के तहत आने वाली नियुक्तियों पर विचार किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि नियुक्ति दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत आती हो। यदि इस तरह के निर्माण को अपनाया जाता है, तो यह दो अनुच्छेदों को अव्यावहारिक बना देगा। इसलिए, यह निर्णय लेने में कि दोनों अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद किसी मामले में लागू होता है, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि जब ऐसी नियुक्ति की गई थी तो क्या इरादा था। क्या इस पद पर नियुक्ति हुई थी, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश की धारा 13 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत एक सिविल न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। यदि यह उत्तरार्द्ध है, तो अनुच्छेद 233 लागू होगा, न कि अनुच्छेद 234। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत एक सिविल न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियों के साथ निवेश किया जा सके। इसलिए, जहां एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जैसा कि एक सिविल न्यायाधीश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करने का भी इरादा है, एक नियुक्ति संहिता की धारा 9 के तहत की जानी है। एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में आपराधिक प्रक्रिया। इसलिए, ऐसी नियुक्ति को नियुक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। यह राज्य के भीतर 'जिला न्यायाधीश' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 236 का अर्थ। नतीजतन, अनुच्छेद 233 एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में एक सिविल न्यायाधीश की नियुक्ति पर लागू होगा। क्योंकि विचाराधीन नियुक्तियां अनुच्छेद 233 का उल्लंघन करके की गई थीं और इसलिए, उन्हें नए अनुच्छेद 233 ए के तहत मान्य माना जाना चाहिए। भार्गव ने हालांकि दलील दी कि यह मानते हुए भी कि अनुच्छेद 233ए लागू होता है, वर्तमान मामले में नियुक्तियां अभी भी अमान्य हैं क्योंकि उन्हें बनाने में राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियमों के नियम 10 और 24 का उल्लंघन किया गया है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है , नियम 7 में प्रावधान है कि उच्च सेवा में भर्ती दो स्रोतों से की जाएगी; (1) राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा, और (2) सीधी भर्ती द्वारा। नियम 10 किससे संबंधित है? नियुक्तियों की संख्या इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भर्ती में दो स्त्रोतों में से प्रत्येक से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और वह अवधि (तीन वर्ष से अधिक नहीं) जिसके लिए भर्ती की जानी है। किए गए आदेश को पहले राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उस नियम के पहले परंतुक में कहा गया है कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या कभी भी सेवा की कुल संख्या के एक–चौथाई से अधिक नहीं होगी और भर्ती की किसी एक अवधि के दौरान इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या उस अवधि के दौरान होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के एक–चौथाई से अधिक नहीं होगी। नियम 24 के अनुसार, राज्यपाल को मूल रिक्तियों की घटना पर नियुक्तियां करनी होती हैं। नियम 13 और 22 के तहत तैयार की गई दो सूचियों के उम्मीदवार उस क्रम में हैं जिसमें पात्र उम्मीदवार संबंधित सूचियों में खड़े हैं। नतीजा यह है कि नियुक्तियों की एक निश्चित संख्या को देखते हुए, पहले

तीन को पदोन्नत ियों से भरा जाना है और चौथा सीधी भर्ती द्वारा चयनित उम्मीदवार द्वारा और इसी तरह। 8 दिसंबर, 1962 के सरकार के पत्र से प्रतीत होता है कि नियम 10 के तहत राज्यपाल ने की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या 18 निर्धारित की, जिनमें से 14 पदोन्नति से और 4 सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी थीं। इन रिक्तियों के लिए भर्ती समाप्त होने वाली अवधि तक होनी थी। तर्क यह था कि नियम 10 के तहत,

भर्ती संभावित है और तीन साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं है और इसलिए, उन पदों की संख्या निर्धारित करते समय जिनके लिए भर्ती की जानी थी, राज्यपाल उस समय खाली पड़ी रिक्तियों को ध्यान में नहीं रख सकते थे। इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों की संख्या का निर्धारण नियम 10 और नियम 24 के विपरीत था और परिणामस्वरूप इस आधार पर चयन समिति की कार्यवाही अमान्य निर्धारण भी अमान्य था।

यह सच है कि 18 पदों में से आयोग द्वारा निर्धारित राज्यपाल, 9 रिक्तियां थीं जिन्हें भरा नहीं गया था और राज्यपाल द्वारा निर्धारित नियुक्तियों की संख्या में शामिल किया गया था।भर्ती में पहले कदम के रूप में, नियम 10 में कोई संदेह नहीं है। यह प्रावधान है कि दोनों स्रोतों में से प्रत्येक से प्रत्येक भर्ती में नियुक्तियों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी।नियम 24 में यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार निर्धारित नियुक्तियों को समिति द्वारा तैयार और उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दो सूचियों में से भरा जाना है।न्यायिक सेवा और सीधी भर्ती के लिए चुने गए लोगों में से चौथा। लेकिन यदि पिछली भर्ती के समय भरे जाने वाले कुछ पद किसी न किसी कारण से खाली रह गए हैं, तो वे रिक्तियां होंगी जिन्हें अगली भर्ती में भरा जा सकता है। वास्तव में नियम 10 में कुछ भी नहीं है या नियम 24 राज्यपाल को उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या में उन्हें शामिल करने से रोकता है। यहां तक कि यदि व्यक्तियों को ऐसे पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है क्योंकि उनकी नियुक्ति वास्तविक नियुक्ति नहीं होगी, तो वे उस पर ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं करेंगे और इसलिए, वे पद तब तक भरे नहीं जाते हैं जब तक कि उनके संबंध में वास्तविक नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। इसलिए, उन्हें नियम 10 के तहत राज्यपाल द्वारा निर्धारित नियुक्तियों की संख्या में शामिल किया जा सकता है। नियम 6(3) में प्रावधान है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से पद खाली छोड़ सकता है या स्थगित कर सकता है। कुछ समय के लिए एक पोस्ट। यदि उस पद को भरने का निर्णय लिया जाता है अगली भर्ती में, कोई कारण नहीं है कि उस नियुक्ति को किसके द्वारा निर्धारित नियुक्तियों की संख्या में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारे विचार में, इस तर्क में कोई वैधता नहीं है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों की संख्या का निर्धारण नियम 10 के विपरीत था या इस तरह के निर्धारण ने चयन समिति की बाद की कार्यवाही को कानून में खराब बना दिया। इसके अलावा, यह तर्क अकादमिक है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि 9 नवंबर, 1960 को 18 पदों में से 9 में 9 न्यायिक अधिकारियों की पुष्टि की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप केवल 9 पद भरा जाना बाकी थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि केवल 9 पद थे जिनके लिए भर्ती की जानी थी और इसलिए, इन 9 पदों में से केवल 2 पद 4 के बजाय सीधी भर्ती के लिए जाएंगे, यदि उन 9 अधिकारियों की पुष्टि नहीं की गई थी। इसलिए यह तर्क खारिज किया जाता है कि नियम 10 के तहत नियुक्तियों का निर्धारण कानून की दृष्टि से गलत था। हम उत्तरदाताओं की वरिष्ठता के दावे के सवाल को छोड़ देते हैं 6 और 7, यदि कोई हो, खुला है क्योंकि यह इस अपील में सख्ती से उत्पन्न नहीं होता है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए केवल यही विवाद थे। हमारे विचार में, उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसलिए अपील खारिज की जाती है। मामले की परिस्थितियों में हम लागत के रूप में कोई आदेश पारित नहीं करते हैं।

आर.के.पी.एस.

अपील खारिज की गई।

विक्रांत ठाकुर की देखरेख में महेश कुमार राठौर द्वारा अनुवादित।